

बाबलू @मुबारिक हुसैन

बनाम

राजस्थान राज्य

12 दिसंबर, 2006

[डॉ. अरिजीत पसायत और एस. एच. कपाडिया, जे. जे.]

भारतीय दंड संहिता, 1860; धारा 85-नशा-बचाव-कब से लिया जा सकता है-हालांकि, आरोपी के क्रूर, शैतानी कृत्यों के लिए कभी भी बहाना नहीं हो सकता है।

अपीलार्थी पर आरोप लगाया गया था कि उसने अपनी पत्नी, तीन बेटियों (सभी नाबालिग) और एक नाबालिग बेटे की एक-एक करके गला घोटकर हत्या कर दी थी। उन पर आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य पर विचार करने पर निचली अदालत ने अपीलार्थी को दोषी पाया। आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के आरोप को साबित पाया गया था और मृत्युदंड लगाया गया था।

निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी और इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 366 के संदर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा की पुष्टि के लिए एक संदर्भ दिया था। अपीलार्थी ने एक अपील भी दायर की और संदर्भ के तहत मामले और अपील दोनों को एक साथ लिया गया और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक सामान्य निर्णय द्वारा निष्पादित किया गया, जिसमें अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.')

की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दी गई मौत की सजा की पुष्टि की गई। इसलिए, वर्तमान अपील दाखिल कि गयी।

वर्तमान अपील में अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिस अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर भरोसा किया गया है वह सही नहीं है। यह

प्रस्तुत किया गया कि कथित एक मंच पर सार्वजनिक रूप से खड़े होने की स्वीकारोक्ति अत्यधिक असंभव है। इसके अलावा, यह कहा गया था कि आरोपी नशे की हालत में था और उसे नहीं पता था कि उसने क्या नहीं किया और इसलिए उसे मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए थी।

दूसरी ओर, राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त के क्रूर और शैतानी कृत्यों से पता चलता है कि वह किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है। जहाँ तक सजा का संबंध है। शराब पीना इस तरह के क्रूर और अमानवीय कृत्यों का बहाना नहीं हो सकता है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

1.1. दोषी केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकता है, लेकिन इसका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित कानून के आधार पर किया जाना चाहिए।

(i) वे परिस्थितियाँ जिनसे अपराध के निष्कर्ष को पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। संबंधित परिस्थितियों को स्थापित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए;

(ii) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है;

(iii) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

(iv) उन्हें हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए जो एक साबित होने की उम्मीद करती है; और

(v) सबूतों की एक श्रृंखला होनी चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धा हो कि सुसंगत निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े। अभियुक्त की निर्दोषता के साथ और यह दिखाना चाहिए कि

सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा। [842 - जी; 843-ए, बी]

हुकुम सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ए. आई. आर (1977) एस. सी. 1063; *एराडू और अन्य वी. हैदराबाद राज्य*, ए. आई. आर. (1956) एस. सी. 316; *एरभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य*, ए. आई. आर(1983) एससी 446; *यू. पी. राज्य बनाम सुखबासी और ओआरएस*, ए. आई. आर (1985) एससी 1224; *बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य*, ए. आई. आर(1987) एससी 350 और *अशोक कुमार चटर्जी बनाम एम. पी. राज्य*, ए. आई. आर. (1989) एस. सी. 1890, संदर्भित।

भगत राम बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर(1954) एससी 621; *सी. चेंगा रेड्डी और अन्य वी. ए. पी. राज्य*, [1996] 10 एस. सी. सी 193; *पदाला वीरा रेड्डी बनाम ए. पी. और अन्य* , ए. आई. आर(1990) एससी 79; *यू. पी. राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव*, ए. आई. आर. (1992) एस. सी. 840; *सर अल्फ्रेड विल्स द्वारा विल्स 'सर्कमस्टैंटिअल एविडेंस' (अध्याय VI); हुनुमंत गोविंद नरगुंडकर और अब्र वी. मध्य प्रदेश राज्य*, ए. आई. आर. (1952) एस. सी. 343 और *शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य*, ए. आई. आर. (1984) एस. सी. 1622, पर निर्भर किया गया ।

2.1 . धारा 361 जो संहिता में एक नया प्रावधान है जिसके तहत अदालत के लिए धारा 360 के प्रावधानों को लागू नहीं करने के लिए "विशेष कारणों" को दर्ज करना अनिवार्य है। इस प्रकार धारा 361 न्यायालय पर यह कर्तव्य डालती है कि वह जहां भी संभव हो धारा 360 के प्रावधानों को लागू करे और - "विशेष कारण" बताएँ यदि वह ऐसा नहीं करता है तो धारा 361 द्वारा विचार किए गए "विशेष कारण" ऐसे होने चाहिए जो अदालत को यह अभिनिर्धारित करने के लिए मजबूर करें कि अपराधी की उम्र, चरित्र और पूर्ववृत्त और वे परिस्थितियाँ जिनमें अपराध किया गया थाको ध्यान में रखते हुए मामले की जांच करने के बाद अपराधी को सुधारना और उसका पुनर्वास करना असंभव है। [844 - बी, सी, डी]

2.2 . अपराधी का व्यक्तित्व जैसा कि उसकी उम्र, चरित्र, पूर्ववृत्त और अन्य परिस्थितियों से प्रकट होता है और अपराधी की व्यवहार्यता सुधार को अनिवार्य रूप से

निर्धारित करने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है इसलिए एक न्यायाधीश को परिस्थितियों, स्थितियों और प्रतिक्रियाओं के साथ अपराधी के व्यक्तित्व को संतुलित करना होता है और उचित सजा का चयन करना होता है। (844 - ई, एफ)

3.1 . 1955 के अधिनियम 26 द्वारा पुरानी संहिता की धारा 367 (5) के संशोधन के बाद, छोड़ने के लिए कारावास की सामान्य सजा दी जा सकती है, ऐसी परिस्थितियों की अनुपस्थिति में जो अपराध की गंभीरता को कम करती हैं। संशोधन के बाद मामला अदालत के विवेक पर छोड़ दिया गया है। हालाँकि, अदालत को सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, और अपने विवेकाधिकार में दो सजाओं में से किसी के लिए भी अपना कारण बताना चाहिए। पूर्व नियम के अंतर्गत हत्या के लिए सामान्य सजा मौत है जो कि अब नहीं है और यह अब अदालत के विवेकाधिकार के भीतर है कि वह इस धारा में निर्धारित दो सजाओं में से किसी एक को पारित करे, लेकिन दो सजाओं में से जो भी वह पारित करता है, न्यायाधीश को एक विशेष सजा देने करने के लिए अपने कारण देने चाहिए। यह संशोधन आई. पी. सी. के तहत सजा को विनियमित करने वाले कानून को प्रभावित नहीं करता है। यह संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है और अब अदालतों को मृत्युदंड नहीं देने के कारणों को विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है; लेकिन वे कम सजा को प्राथमिकता देते हुए ठोस न्यायिक विचारों से अनदेखा कर आस्थगित नहीं हो सकते हैं।

3.2 . अदालत को दी गई सजा के कारण बताने की आवश्यकता होती है और मौत की सजा के मामले में "विशेष कारण" बताए जाने की आवश्यकता होती है, अर्थात्, केवल विशेष तथ्य और परिस्थितियां में ही मौत की सजा को पारित करने की अनिवार्यता होगी । [845 - डी, ई]

एडिगा अनाम्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [1974] 4 एस. सी. सी. 443 और *बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य*, [1980] 2 एस. सी. सी. 684, पर निर्धारित किया गया

3.3 . सज़ा को गम्भीर और कम करने वाली परिस्थितियों का एक संतुलन तैयार करना होगा और ऐसा करने के लिए कम करने वाली परिस्थितियों को पूरा महत्व देना होगा और विकल्प का उपयोग करने से पहले गम्भीर और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच एक न्यायसंगत संतुलन बनाना होगा। इन दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनका उत्तर दिया जा सकता है, (ए) क्या अपराध के बारे में कुछ असामान्य है जिसके कारण आजीवन कारावास की सजा अपर्याप्त है और मृत्युदंड की मांग करती है? और (ख) अपराध की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अपराधी के पक्ष में बोलने वाली और सज़ा को कम करने वाली परिस्थितियों को अधिकतम वजन के बावजूद मौत की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। [846 - एफ, जी]

4.1 . अपराध और सजा के बीच का अनुपात एक ऐसा लक्ष्य है जिसका सम्मान मुख्य सिद्धांतों में किया जाता है और गलत धारणाओं के बावजूद, उसका सज़ा के निर्धारण में एक मजबूत प्रभाव बना हुआ है। सभ्य समाजों में सभी गंभीर अपराधों को समान गंभीरता के साथ दंडित करने की प्रथा अब अज्ञात है, लेकिन आनुपातिकता के सिद्धांत का ऐसा कट्टरपंथी विचलन हाल के दिनों में ही कानून से विलुप्त हुआ है। अब एक भी गंभीर उल्लंघन के बारे में सोचा जाता है कि इसके लिए समान रूप से कठोर उपायों की आवश्यकता है। [849 - एफ, जीजे

5.1 . नशे की लत से बचाव का लाभ केवल तब लिया जा सकता है जब नशे की वजह से अभियुक्त अपराध के लिए अपेक्षित 'इरादा' खो देता है। नशे के कारण के बारे में सबूत की जिम्मेदारी आरोपी पर है जिसके कारण आरोपी विशेष इरादे को बनाने में विशेष ज्ञान रखने में असमर्थ हो गया था। [850 - सी, डी]

5.2 . अभियुक्त के शैतानी कृत्य का नशे की लत कभी भी क्रूरता का बहाना नहीं हो सकती। अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा किए गए क्रूर कार्य गर्भधारण में शैतानी और निष्पादन में क्रूर होते हैं। ये कृत्य न केवल क्रूर थे, बल्कि अमानवीय भी थे, जिनका कोई पछतावा नहीं था। केवल इसलिए कि वह प्रासंगिक समय पर नशे में होने

का दावा करता है, यह किसी भी तरह से कमजोर नहीं होता है क्योंकि आई. पी. सी. की धारा 85 में क्या प्रावधान किया गया है, बल्कि इसलिए कि एक के बाद एक पांच लोगों की जान ले ली गई और वह भी चार छोटे बच्चों की। यह मामला मौत की सजा देने के लिए दुर्लभतम से दुर्लभतम श्रेणी के अंतर्गत आता है। [850 - जी; 851-ए, बी]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील सं. 1302-2006 .

उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 27.7.2006 से डी. बी. सी. आर. एल. में जोधपुर में राजस्थान के लिए न्यायपालिका। हत्या संदर्भ सं. 2-2006 और डी. बी. सी. आर. एल जेल अपील सं. 447/2006।

अपीलार्थी की ओर से - वी. रामसुब्रमण्यन।

अरुणेश्वर गुप्ता, नवीन कुमार सिंह, मुकुल सूद, शाश्वत गुप्ता और उत्तरदाता की ओर से - शिखा टंडन।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया था, लीव मंजूर।

इस अपील में चुनौती दी गयी जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी. ') की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए अपीलार्थी को दी गई मौत की सजा की पुष्टि करने वाले फैसले को दी गई है। निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी और इसलिए, पुष्टि के लिए एक संदर्भ दिया था, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 366 के संदर्भ में।

अपीलार्थी ने एक अपील भी दायर की और संदर्भ के तहत मामले और अपील दोनों को एक साथ लिया गया और एक सामान्य निर्णय द्वारा निष्पादित किया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने अपनी पत्नी अनीशा, की हत्या कर दी, तीन बेटियाँ नामतः गुल्फशा, निशा और अंता @मुन्नी जिनकी आयु क्रमशः 9 वर्ष, 6 वर्ष और 4 वर्ष है और बेटा बाबू जिसकी आयु ढाई वर्ष है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश

(फास्ट ट्रैक), नागौर ने आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध करने के आरोप को साबित पाया था और मौत की सजा सुनाई थी।

संक्षेप में अभियोजन संस्करण इस प्रकार है:

अलादीन (पीडब्लू-1) ने लगभग 6 बजे पुलिस स्टेशन, नागौर में एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के साथ कहा गया कि 9.12.2005 अपीलार्थी बबलू ने अपनी पत्नी और बच्चों को पीटा। लेकिन उनके हस्तक्षेप पर उन्हें बचा लिया गया। उन्होंने बबलू को कुख्यात चरित्र वाला व्यक्ति बताया। यह भी बताया गया कि सुबह लगभग 5 बजे उसका भाई अपीलार्थी बबलू चिल्लाते हुए घर से बाहर आया और घोषणा की कि उसने एक-एक करके सभी पांचों कमीनों का गला घोटकर हत्या कर दी है। उसने अपनी पत्नी अनीशा, बेटियों गुल्फशा, निशा, अंता उर्फ मुन्नी और बेटे बाबू की हत्या कर दी। शवों को प्रत्येक पैर के अंगूठे को धागे से बांधते हुए गद्दे पर रखा गया था। इस सूचना पर पुलिस ने आई. पी. सी. की धारा 30 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई की। जांच पड़ताल की। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तीन डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने सभी पांचों शवों का पोस्टमॉर्टम किया। अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया। सामान्य जाँच के बाद पुलिस ने अपीलार्थी के खिलाफ धारा 302 आई. पी. सी. के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया। ऐसा करने पर अपीलार्थी पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक), नागौर की अदालत द्वारा धारा 302 आई. पी. सी. के तहत दंडनीय अपराध के आरोप का मुकदमा चलाया गया। नेतृत्व किए गए साक्ष्य पर विचार करने पर निचली अदालत अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध का दोषी पाया।

विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित परिस्थितियों पर भरोसा किया दोषी ठहराया गया।

(1) अपीलार्थी द्वारा मुराद खान के समक्ष किया गया अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति (पीडब्लू-1), बबलू कलवा (पीडब्लू-2), मोहम्मद शरीफ (पीडब्लू-3) और अल्लादीन (पीडब्लू-4)।

(2) अपीलार्थी की उस घर में उपस्थिति, जहाँ कथित घटना हुई थी।

(3) अपीलार्थी के कब्जे से पत्नी के कान की बाली की बरामदगी ।

निर्देश और अपील की सुनवाई के समय अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा लिया गया प्राथमिक रुख यह था कि अभियोजन पक्ष द्वारा निर्भर किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति सही नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि कथित एक मंच पर सार्वजनिक रूप से खड़े होने की स्वीकारोक्ति अत्यधिक असंभव है। उच्च न्यायालय ने पाया कि मुराद खान (पीडब्लू-1) और बबलू (पीडब्लू-2) के साक्ष्य ठोस और विश्वसनीय थे। पीडब्लू-1 पड़ोसी था और पीडब्लू-2 अभियुक्त-अपीलार्थी का भाई है। इस बात का कोई कारण नहीं है कि वे एक असत्य बयान देकर अभियुक्त-अपीलार्थी को गलत तरीके से क्यों फंसाते। इसके अलावा, अपीलार्थी के व्यवहार के बारे में पीडब्लू-1 का साक्ष्य प्रासंगिक था। तीसरी परिस्थिति अपीलार्थी के कब्जे से आभूषण की बरामदगी थी। उच्च न्यायालय के अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा उजागर की गई परिस्थितियों ने परिस्थितियों की एक पूरी श्रृंखला प्रस्तुत की। यद्यपि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि भले ही अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया हो, मृत्युदंड देने का कोई विशेष कारण नहीं था। इस न्यायालय द्वारा *माची सिंह और अन्य वी. पंजाब राज्य*, [1983] 3 एस. सी. सी. 470 और *बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य*, [1980] 2 एससीसी 684 पर परिपेक्ष में उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर विचार किया। *राजस्थान राज्य बनाम खेराज राम*, [2003] 8 एस. सी. सी. 224 के निर्णय का भी संदर्भ दिया गया था। उच्च न्यायालय का विचार था कि अपीलार्थी ने सबसे क्रूर और शैतानी तरीके से काम किया था। उन्होंने जानबूझकर योजना बनाई और सावधानीपूर्वक इसे निष्पादित किया। इस तरह के वीभत्स कृत्यों के लिए कोई पछतावा

भी नहीं था। इसके विपरीत, उन्होंने जो किया था, उससे वे संतुष्ट थे। उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने के अपने कृत्य की घोषणा की। तदनुसार, मौत की सजा की पुष्टि की गई।

अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष लिए गए रुख को इस अपील में दोहराया गया। इसके अलावा, यह कहा गया था कि आरोपी नशे की हालत में था और उसे नहीं पता था कि उसने क्या किया और इसलिए उसे मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए थी।

वही अभियोजन ने राज्य की ओर से यह दलील पेश की कि जहाँ तक सजा का संबंध है। शराब पीना एक बहाना नहीं हो सकता है ऐसे क्रूर और अमानवीय कृत्य के लिए । और ऐसे कृत्य के लिए वे किसी तरह की मुरव्वत या नर्मी के हकदार नहीं हैं ।

इस न्यायालय द्वारा लगातार यह निर्धारित किया गया है कि जहां कोई मामला वस्तुतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्धारित हो, अपराध के अनुमान को उचित ठहराया जा सकता है केवल तभी जब सभी दोषपूर्ण तथ्य और परिस्थितियाँ पाई जाती हैं अभियुक्त की निर्दोषता के विद्रोह या किसी अन्य के अपराध के साथ असंगत व्यक्ति के निर्दोषता के विद्रोह हो।(हुकुम सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ए. आई. आर.(1977) एससी 1063; एराडू वी. हैदराबाद राज्य, ए. आई. आर. (1956) एस. सी. 316; एरभद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, ए. आई. आर.(1983) एससी 446; यू. पी. राज्य बनाम सुखबासी और ओआरएस, ए. आई. आर. (1985) एससी 1224; बलविंदर सिंह बनाम/पंजाब राज्य, ए. आई. आर.(1987) एससी 350; अशोक कुमार चटर्जी बनाम एम. पी. राज्य, ए. आई. आर. (1989) एस. सी. 1890। जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के अपराधी होने के बारे में कोई निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें उचित संदेह से परे साबित करना होगा और यह दिखाया जाना होगा कि प्रमुख तथ्य के साथ निकटता से जुड़े तथ्यों से अनुमान लगाने की कोशिश की गई परिस्थितियाँ। भगत राम बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. (1954) एस. सी. 621 में यह निर्धारित किया गया था कि जहां मामले का निष्कर्ष परिस्थितियों पर निर्भर करता है परिस्थितियों संचयी प्रभाव इस तरह होना चाहिए

कि - अभियुक्त की निर्दोषता को नकारना और अपराधों के साबित होने की विफलता का कोई भी उचित संदेह ना हो।

इस न्यायालय के *सी. चेंगा रेड्डी वी. ए. पी. राज्य* [1996] 10 एस. सी. सी. 193, और अन्य मामलों में दिए गए फैसले का भी संदर्भ दे सकते हैं। जिसमें यह इस प्रकार देखा गया:

" परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले में, तय किया गया कानून यह है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूरी तरह से साबित किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए। इसके अलावा, सभी परिस्थितियाँ पूर्ण होनी चाहिए और साक्ष्य की श्रृंखला में कोई अंतर नहीं रहना चाहिए। आगे यह साबित हुआ कि परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए और उसकी निर्दोषता के साथ पूरी तरह से असंगत होनी चाहिए...।

पदाला वीरा रेड्डी बनाम ए. पी. राज्य और अन्य, ए. आई. आर. (1990) एस. सी. 79 में यह निर्धारित किया गया था कि जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, तो साक्ष्य को निम्नलिखित परीक्षणों को संतुष्ट करना चाहिए:

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है उन्हें बुनियादी तौर पर दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए;

(2) वे परिस्थितियाँ एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो कि बेचूक अपराधी के दोषी होने की ओर इशारा करे;

(3) संचयी रूप से ली गई परिस्थितियों को एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानव संभावनाओं में अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और किसी के द्वारा नहीं;

और;

(4) दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त के अपराध को साबित करने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में अपूर्ण और असमर्थ होने चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए बल्कि अपराधी की निर्दोषता से असंगत होना चाहिए।

यू. पी. राज्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव, ए. आई. आर. (1992) एस. सी. 840, में यह बताया गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन करने में बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए। और यदि साक्ष्य दो निष्कर्षों के लिए यथोचित रूप से सक्षम है, तो अभियुक्त के पक्ष में साक्ष्य को स्वीकार किया जाना चाहिए। यह भी बताया गया कि जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित पाया जाना चाहिए और इस तरह से स्थापित सभी तथ्यों का संचयी प्रभाव केवल अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए।

सर ऐल्फ्रेड विल्ज़ ने अपनी किताब "विल्ज़' परिस्थितिजन्य साक्ष्य"(चैप्टर vi) में निम्नलिखित नियमों की सूची दी जिन्हें परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए (1) किसी भी कानूनी निष्कर्ष के आधार के रूप में कथित तथ्यों को स्पष्ट रूप से साबित किया जाना चाहिए और तथ्य प्रोबेन्डम से जुड़े उचित संदेह से परे पाया जाना चाहिए। तथ्य प्रोबेन्डम के साथ; (2) सबूत का भार हमेशा उस पक्ष पर होता है जो किसी भी तथ्य के अस्तित्व का दावा करता है, जो कानूनी जवाबदेही का अनुमान लगाता है; (3) सभी मामलों में, चाहे वह प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य सबूत का हो, सबसे अच्छा सबूत पेश किया जाना चाहिए जिसे मामले की प्रकृति स्वीकार करती है; (4) अपराध के निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए, दोषपूर्ण तथ्यों को आरोपी की निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए और किसी और परिकल्पना की स्पष्टीकरण का समर्थन करने में असमर्थ होना चाहिए। (5) यदि अभियुक्त के अपराध के बारे में कोई उचित संदेह है, तो वह बरी होने के अधिकार का हकदार है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषसिद्धि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, लेकिन इसका परीक्षण संबंधित कानून के तराजू पर खरा उतरना चाहिए जो कि इस न्यायालय द्वारा 1952 में दिए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संदर्भ में ।

हनुमंत गोविंद नरगुंडकर और अन्य वी. मध्य प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. (1952) एस. सी. 343, जिसमें यह अवलोकन किया गया :

" यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का है, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पहली बार में पूरी तरह से स्थापित होने चाहिए और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। और, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि बाकी हर परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए अथवा उसके जिसे साबित करने का प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में, अब तक सबूतों की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ती है और वह ऐसा होना चाहिए जो यह दिखा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर.(1984) एससी 1622 में बाद के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है। इसमें, परिस्थितिजन्य साक्ष्य को सम्बोधित करने के दौरान, यह माना गया है कि यह साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर थी कि श्रृंखला पूरी हो गई है और अभियोजन में कमी की दुर्बलता को झूठे बचाव या याचिका से ठीक नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय के शब्दों में दि गयी पूर्ववर्ती शर्तें, दोषसिद्धि से पहले परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो सकती हैं, पूरी तरह से स्थापित की जानी चाहिए। वे इस प्रकार हैं:

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। संबंधित परिस्थितियों को स्थापित किया जाना चाहिए या किया जाना ही चाहिए ना की किया जा सकता है;

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराधी होने के परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए अर्थात् उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर समझने योग्य नहीं होना चाहिए सिवाए इसके कि अभियुक्त दोषी है ;

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

(4) उन्हें एक को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को शामिल नहीं करना चाहिए; जिसे सिद्ध किया जाए; और

(5) सबूतों की एक श्रृंखला होनी चाहिए ताकि कोई भी चीज़ न छोटे जो कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए उचित आधार हो और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

एकमात्र अन्य बात जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या मृत्यु विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा उचित है।

आई. पी. सी. की धारा 302 हत्या के लिए मौत या आजीवन कारावास की सजा निर्धारित करती है। ऐसा करते समय, संहिता न्यायालय को उसके समुपयोग के बारे में निर्देश देती है। पिछले तीन दशकों में संहिता में जो बदलाव हुए हैं, वे स्पष्ट हैं। यह इंगित करता है कि सांसद समकालीन आपराधिक विचारों और आंदोलन पर ध्यान दे रही है। यह समझना मुश्किल नहीं है कि संहिता में आजीवन कारावास की ओर एक निश्चित रुख है। मौत की सजा को आम तौर पर खारिज कर दिया जाता है और केवल "विशेष कारणों" के लिए लगाया जा सकता है, जैसा कि धारा 354 (3) में प्रदान किया गया है। संहिता में एक और प्रावधान है जो महत्वपूर्ण रूप से उपयोग करता है अभिव्यक्ति "विशेष कारण" का। यह धारा 361 है। 1973 की संहिता की धारा 360 वस्तुतः दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 562 (संक्षेप में "पुरानी संहिता") को फिर से अधिनियमित करती है। धारा 361, जो संहिता में एक नया प्रावधान है, अदालत के लिए धारा 360 के प्रावधानों को लागू नहीं करने के लिए "विशेष कारणों" को दर्ज करना अनिवार्य बनाता है। इस प्रकार धारा 361 न्यायालय पर यह कर्तव्य डालती है कि वह जहां भी संभव हो धारा 360 के प्रावधानों को लागू करे और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो "विशेष कारण" बताए। धारा 360 के संदर्भ में, धारा 361 द्वारा विचार किए गए "विशेष कारण" ऐसे होने चाहिए जो अदालत को यह अभिनिर्धारित करने के लिए मजबूर करें कि अपराधी की उम्र, चरित्र और पूर्ववृत्त और उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते

हुए जिनमें अपराध किया गया था, मामले की जांच करने के बाद अपराधी को सुधारना और पुनर्वास करना असंभव है। यह विधायिका द्वारा कुछ संकेत है कि अपराधियों का सुधार और पुनर्वास, न कि केवल प्रतिरोध, अब हमारे देश में आपराधिक न्याय के प्रशासन के प्रमुख उद्देश्यों में से हैं। धारा 361 और धारा 354 (3) दोनों ने एक ही समय में कानून-पुस्तक में प्रवेश किया है और वे अपराध विज्ञान में नई प्रवृत्तियों की विधायिका द्वारा स्वीकृति की उभरती तस्वीर का हिस्सा हैं। इसलिए, यह मान लेना गलत नहीं होगा कि अपराधी का व्यक्तित्व, जैसा कि उसकी उम्र, चरित्र, पूर्ववृत्त और अन्य परिस्थितियां और सुधार के लिए अपराधी की व्यवहार्यता से, आवश्यक प्रकट होता है। अनिवार्य रूप से दी जाने वाली सजा को निर्धारित करने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं। विशेष कारणों का इन कारकों से कुछ संबंध होना चाहिए, आपराधिक न्याय जटिल मानवीय समस्याओं और विविध मनुष्यों से संबंधित है। एक न्यायाधीश को परिस्थितियों, स्थितियों और प्रतिक्रियाओं के साथ अपराधी के व्यक्तित्व को संतुलित करना होता है और उसके लिए उपयुक्त सजा का चयन करना होता है।

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1955 (1955 का 26) द्वारा पुरानी संहिता की धारा 367 (5) के संशोधन से पहले, जो मृत्युदंड के साथ दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर लागू हुआ था, यदि अदालत ने आरोपी को मृत्युदंड के अलावा किसी अन्य सजा की सजा सुनाई थी, तो निर्णय में मृत्युदंड की सजा पारित नहीं किए जाने का कारण बताया जाना था। 1955 के अधिनियम 26 द्वारा पुराने धारा 367 (5) संहिता के संशोधन के बाद, यह अभिनिर्धारित करना सही नहीं है कि ऐसी परिस्थितियों के अभाव में जो अपराध की गंभीरता को कम करती हैं आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है। संशोधन के बाद, यह मसला न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। हालाँकि, अदालत को सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, और अपने विवेकाधिकार में दो सजाओं में से किसी के लिए भी अपना कारण बताना चाहिए। इसलिए, पूर्व नियम कि हत्या के लिए सामान्य सजा मौत है, अब लागू नहीं है और यह अब अदालत के विवेक पर निर्धारित है कि वह इस धारा में निर्धारित दो सजाओं में से किसी एक को पारित करे; लेकिन दो सजाओं में से जो भी वह पारित करता है, न्यायाधीश को एक विशेष दंड देने के लिए

अपने कारण देने चाहिए। पुरानी संहिता की धारा 367 (5) का संशोधन आईपीसी के तहत दंड को विनियमित करने वाले कानून को प्रभावित नहीं करता है। यह संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है और अब अदालतों पर मृत्युदंड न देने के कारणों को विस्तार से बताने की आवश्यकता है; लेकिन वे ठोस स्थापित न्यायिक विचारों से अलग नहीं हो सकते हैं जिसमें कम सज़ा चुन्ने को महत्ता दी गयी है ।

संहिता की धारा 354 (3) विधायी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है। पुरानी संहिता के अंतर्गत नीति जो 1.4.1974 से तुरंत पहले लागू थी, जिसके अनुसार मृत्यु या आजीवन कारावास दोनों ही वैकल्पिक सजाएँ हत्या के लिए सामान्य सजा थी। अब, संहिता की धारा 354 (3) के तहत हत्या के लिए सामान्य सजा आजीवन कारावास है और मृत्युदंड एक अपवाद है। अदालत को दी गई सजा के कारण बताने की आवश्यकता होती है और मौत की सजा के मामले में "विशेष कारण" बताए जाने की आवश्यकता होती है, यानी केवल विशेष तथ्य और परिस्थितियों में मौत की सजा को पारित करने की प्रमाणिकता देगा। इन संहिता में क्रमिक विधायी परिवर्तन के प्रकाश में समझने की आवश्यकता है उन न्यायिक निर्णय को जो 1955 के अधिनियम 26 और फिर 1974 के अधिनियम 2 के पूर्व में यह न्यायालय के द्वारा दिए गए ।

एडिगा अनम्मा बनाम ए. पी. राज्य, [1974] 4 एस. सी. सी. 443, जिस्म यह देखा गया: (एससीसी पीपी।453-54 , पैरा 26)

" 26. आइए हम वर्तमान में भारतीय कानून के तहत मौत की सजा के खिलाफ सकारात्मक संकेतकों को स्पष्ट करें। जहाँ हत्यारा बहुत छोटा है या बहुत बूढ़ा है, दया या दंडात्मक न्याय उसकी मदद करता है। जहाँ अपराधी सामाजिक-आर्थिक, मानसिक या दंडात्मक मजबूरियों से पीड़ित है जो कानूनी अपवाद को आकर्षित करने या अपराध को कम करने के लिए अपर्याप्त है, न्यायिक क्षमादान की अनुमति है।

अन्य सामान्य समाजिक दबा जिसको की न्यायिक नज़रिए की आवश्यकता है, जिसका एक विस्तारक प्रभाव हो, ऐसे विशेष रूप से मामले कम दंड के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कि असाधारण विशेष न्यायिक प्रक्रिया में अपराधी को अत्यधिक लंबे समय तक मौत की सजा के सिर पर लटका दिया गया है, अदालत को राज़ी का सकता है दयालु बर्ताव रखने

को। इसी तरह, यदि अपराध में शामिल और इसी तरह स्थित अन्य लोगों को आजीवन कारावास का लाभ मिला है या यदि अपराध केवल रचनात्मक है, धारा 302 के तहत होने के नाते, धारा 149 के साथ पढ़ा जाता है, या फिर आरोपी ने अचानक दूसरे के उकसावे के तहत बिना किसी पूर्व-विचार के काम किया है, तो शायद अदालत मानवीय रूप से आजीवन कारावास का विकल्प चुन सकती है, भले ही पत्नी की बेवफाई का उचित कारण या वास्तविक संदेह ने अपराधी को अपराध के लिए मजबूर कर दिया हो। दूसरी ओर, उपयोग किए गए हथियार और उनके उपयोग का तरीका, अपराध की भयानक विशेषताएं और पीड़ित की असहाय स्थिति, एक कठोर सजा के लिए कानून के नज़रिए को मजबूत करते हैं। हम स्पष्ट रूप से एक समूह में नहीं डाल सकते न्यायिक कंप्यूटर में ऐसी सभी स्थितियाँ क्योंकि वे ज्योतिषीय हैं , एक अपूर्ण और लहरदार समाज में अभेद्य। जीवन या मृत्यु पर एक कानूनी नीति को तदर्थ मनोदशा या व्यक्तिगत झुकाव के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है और इसलिए हमने प्रतिशोधात्मक क्रूरता को त्यागते हुए, निवारक पंथ में संशोधन करते हुए और अत्यधिक और अपरिवर्तनीय दंड के खिलाफ प्रवृत्ति को बढ़ाते हुए यथासंभव वस्तुनिष्ठ बनाने की कोशिश की है।”

बचन सिंह के मामले में यह देखा गया है कि: (एस. सी. सी पी. 751, पैरा 209):

" मानव जीवन की गरिमा के लिए एक वास्तविक और स्थायी चिंता कानून के माध्यम से जीवन लेने के प्रतिरोध को प्रस्तुत करती है। दुर्लभतम मामलों को छोड़कर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए जब वैकल्पिक विकल्प निर्विवाद रूप से बंद हो।”

बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों का एक संतुलन तैयार करना होगा और ऐसा करने के लिए कम करने वाली परिस्थितियों को पूरा महत्व देना होगा और विकल्प का उपयोग करने से पहले बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच एक न्यायसंगत संतुलन बनाना होगा। इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उत्तर दिए जा सकते हैं, (क) क्या अपराध के बारे में कुछ असामान्य है जो आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त

बनाता है और मौत की सजा की माँग करता है? ; और (ख) क्या अपराध की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अपराधी के पक्ष में बोलने वाली कम करने वाली परिस्थितियों को अधिकतम महत्व देने के बाद भी मृत्युदंड देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है?

एक अन्य निर्णय जो स्पष्ट रूप से मौत की सजा के सवाल से संबंधित है, *माची सिंह का मामला* (उपरोक्त) है।

माछी सिंह (उपरोक्त) और *बचन सिंह* (उपरोक्त) मामलों में इस सवाल पर विचार करते समय दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जब यह सम्बोधित किया जाना हो की क्या मामला दुर्लभतम श्रेणी की ओर संकेत करता है।

माची सिंह (उपरोक्त) मामले में यह देखा गया था: (एस. सी. सी पी. 489, पैरा 39):

निम्नलिखित प्रश्न एक परीक्षण के रूप में पूछे और उत्तर दिए जा सकते हैं इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए की क्या मामला 'दुर्लभतम में दुर्लभतम' मामला हैं जिसमें मौत की सजा दी जा सकती है:

(क) क्या अपराध के बारे में कुछ असामान्य है जो ऐसा करता है आजीवन कारावास की सजा अपर्याप्त है और मृत्युदंड की माँग करती है?

(ख) अपराध की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अपराधी के पक्ष में सजा को कम करने वाली परिस्थितियों को अधिकतम महत्व देने के बाद भी मौत की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

बचन सिंह के मामले (उपरोक्त) से उभरने वाले निम्नलिखित दिशानिर्देशों को प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर लागू किया जाना चाहिए जहां प्रश्न में मृत्युदंड की स्थिति उत्पन्न होती है: (एस. सी. सी पी. 489, पैरा 38):

((i) मृत्युदंड को अत्यधिक दोषी होने के मामले में गंभीरतम दंड के अलावा किसी और रूप में देने की आवश्यकता नहीं है।

((ii) मृत्युदंड का विकल्प चुनने से पहले 'अपराधी' की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। 'अपराध' की परिस्थितियाँ के साथ।

(ग) आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड अपवाद है। मृत्युदंड तभी दिया जाना चाहिए जब आजीवन कारावास अपर्याप्त सजा लगने लगे अपराध की प्रासंगिक परिस्थितियाँ के विचाराधीन। और तब और सिर्फ तब, जब केवल प्रदान की गई अपराध प्रकृति और अत्यधिक दोषी होने के मामले को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी से अभ्यास किया जाता है और आजीवन कारावास की सजा देने का विकल्प नहीं हो सकता है।

(iv) सजा को गम्भीर करती और कम करने वाली परिस्थितियों का एक संतुलन तैयार करना होगा और ऐसा करने के लिए कम करने वाली परिस्थितियों को पूरा महत्व देना होगा और विकल्प तैयार करने से पहले बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच एक न्यायसंगत संतुलन बनाना होगा, निर्णय लेने से पूर्व।

दुर्लभतम मामलों में जब समुदाय की सामूहिक अंतरात्मा इतनी हैरान हो जाती है कि वह न्यायिक शक्ति केंद्र के धारकों से अपेक्षा करेगी कि वे वांछनीयता के संबंध में उनकी व्यक्तिगत राय मृत्युदंड की आवश्यकता या मृत्युदंड बरकरार रखने पर होने के बावजूद, मृत्युदंड दिया जा सकता है। समुदाय निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसी भावना का समर्थन कर सकता है

(1) जब हत्या एक अत्यंत क्रूर, विचित्र तरीके से की जाती है, शैतानी, विद्रोही या कायर्तापूर्ण तरीके से ताकि तीव्र और उत्तेजित किया जा सके समुदाय का अत्यधिक आक्रोश।

(2) जब हत्या किसी ऐसे उद्देश्य के लिए की जाती है जो पूरी तरह से भ्रष्टता और नीचता को दर्शाता है; उदाहरण के लिए, पैसे या इनाम के लिए भाड़े के हत्यारे द्वारा हत्या या किसी ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए निर्मम हत्या, जिसके खिलाफ हत्यारा हावी स्थिति में या विश्वास की स्थिति में है, या मातृभूमि के साथ विश्वासघात के लिए हत्या की जाती है।

(3) जब अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक के किसी सदस्य की हत्या की जाती है समुदाय आदि, व्यक्तिगत कारणों से नहीं बल्कि ऐसी परिस्थितियाँ जो सामाजिक आक्रोश पैदा करती हैं, या 'दुल्हन को जलाने' या 'दहेज हत्या' के मामलों

में या जब एक बार फिर से दहेज निकालने के लिए या किसी अन्य महिला से शादी करने के लिए फिर से शादी करने के लिए हत्या की जाती है मोह के कारण।

(4) जब अपराध अनुपात में बहुत बड़ा हो। उदाहरण के लिए जब एक परिवार के सभी या लगभग सभी सदस्यों या किसी विशेष जाति, समुदाय या इलाके के बड़ी संख्या में व्यक्तियों की कई हत्याएं होती हैं ।

(5) जब हत्या का शिकार एक निर्दोष बच्चा, या एक असहाय महिला या बूढ़ा या कमजोर व्यक्ति या एक व्यक्ति जिसे हत्यारा हावी स्थिति में है या एक सार्वजनिक व्यक्ति जिसे आम तौर पर प्यार किया जाता है और समुदाय द्वारा सम्मान किया जाता हो ।

यदि उपरोक्त प्रस्तावों के आलोक में सभी परिस्थितियों के समग्र वैश्विक दृष्टिकोण को लेते हुए और उत्तरों को ध्यान में रखते हुए मामले की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि मौत की सजा की आवश्यकता होती है, अदालत ऐसा करने के लिए आगे बढ़ेगी। एक दोषी जीवन और मृत्यु के बीच झूलता है तब अपराध की गंभीरता और पर्याप्त सजा देने का सवाल विचार के लिए आता है। मानव जाति प्रकृति की स्थिति से एक सभ्य समाज की ओर स्थानांतरित हो गई है। यह अब बहुमत की भौतिक राय नहीं है जो किसी नागरिक को दोषी ठहराकर और उसे कारावास की सजा देकर उसकी स्वतंत्रता छीन लेती है। एक प्रणाली में एक मुकदमे में दोषी ठहराए जाने के बाद सजा का हकदार होना कानून के दोनो पक्षकारों को पर्याप्त सुनवाई के बाद अदालत कक्ष में शांत विचार-विमर्श का परिणाम है, अभियुक्त के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं, अभियुक्त पक्ष को अपनी बेगुनाही स्थापित करके आरोपों का सामना करने का अवसर दिया जाता है। यह शांत विचार-विमर्श और जानकार व्यक्ति यानी न्यायाधीश द्वारा वाद की जांच का परिणाम है जो निर्धारण की ओर ले जाता है और न्यायोचित है।

अपराध और सजा के बीच अनुपात का सिद्धांत न्यायपूर्ण रेगिस्तान का एक सिद्धांत है जो प्रत्येक आपराधिक सजा की नींव के रूप में कार्य करता है। आपराधिक न्याय के सिद्धांत के रूप में यह इस सिद्धांत से शायद ही कम परिचित या कम महत्वपूर्ण है ये सिद्धांत कि केवल दोषियों को ही दंडित किया जाना चाहिए। वास्तव में, यह आवश्यकता

कि सजा असमान रूप से बड़ी न हो, जो कि न्यायपूर्ण रेगिस्तान का एक परिणाम है, उसी सिद्धांत द्वारा निर्धारित की जाती है जो निर्दोष को सजा की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि आपराधिक आचरण के लिए जो भी सजा योग्य है, उससे अधिक कोई भी सजा अपराध के बिना सजा है। आपराधिक कानून सामान्य रूप से प्रत्येक प्रकार के अपराधी की दोषसिद्धि के अनुसार दायित्व निर्धारित करने में आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करता है। यह आम तौर पर न्यायाधीश को प्रत्येक मामले में एक सजा पर पहुंचने में कुछ महत्वपूर्ण विवेक की स्वतंत्रता देता है, संभवतः उन सजाओं के लिए अनुमति देने के लिए जो प्रत्येक मामले के विशेष तथ्यों द्वारा उठाए गए दोष के अधिक सूक्ष्म विचारों को दर्शाते हैं। न्यायाधीश संक्षेप में इस बात की पुष्टि करते हैं कि सजा हमेशा दी जानी चाहिए। अपराध के अनुकूल होने के लिए; फिर भी व्यवहार में सजा काफी हद तक अन्य विचारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कभी-कभी यह अपराधी की सुधारात्मक आवश्यकताएं होती हैं जो एक सजा को सही ठहराने के लिए पेश की जाती हैं। कभी-कभी उसे प्रचलन से बाहर रखने की वांछनीयता, और कभी-कभी यातायात भी उसके अपराध का परिणाम होता है। अनिवार्य रूप से ये विचार आधार के रूप में सिर्फ रेगिस्तान से प्रस्थान का कारण बनते हैं जो सजा देना और स्पष्ट अन्याय के मामले पैदा करने जैसी परिस्थिति पैदा करती है जो गंभीर और व्यापक हैं।

अपराध और सजा के बीच अनुपात एक ऐसा लक्ष्य है जिसका सिद्धांत के रूप में सम्मान किया जाता है, और गलत धारणाओं के बावजूद, इसका सजा के निर्धारण में एक मजबूत प्रभाव बना हुआ है। सभी गंभीर अपराधों को समान गंभीरता के साथ दंडित करने की प्रथा अब सभ्य समाजों में अज्ञात है, लेकिन इस तरह के एक कट्टरपंथी प्रस्थान आनुपातिकता का सिद्धांत हाल के दिनों में ही कानून से गायब हो गया है। अब भी एक गंभीर उल्लंघन जिसके बारे में सोचा जा सकता है कि इसके लिए समान रूप से कठोर उपायों की आवश्यकता है। किसी भी गंभीर मामले में सबसे अधिक गंभीरता के दंड से कम कुछ भी असमान दंड माना जाता है की सहनशीलता का एक उपाय है जो की अनुचित और नासमझता है। लेकिन यह उन विचारों से काफी अलग है जो कि दंड को अनुचित बनाते हैं जब यह अपराध के अनुपात से बहार है। समान रूप से अनुपातहीन सजा के कुछ बहुत ही अवांछनीय अव्यावहारिक परिणाम हैं।

आई. पी. सी. की धारा 85 ऐसे व्यक्ति के कार्य से संबंधित है जो निर्णय लेने में असमर्थ है, उसकी इच्छा के विरुद्ध होने वाले नशा के कारण। जैसा कि प्रावधान के शीर्षक से ही पता चलता है, नशा उसकी इच्छा के खिलाफ रहा होगा और/या जिस चीज को उसने नशे में डाला था, उसे उसकी जानकारी के बिना दिया गया था। अपीलार्थी की जानकारी के बिना मादक पदार्थ दिए जाने के बारे में वर्तमान मामले में कोई विशिष्ट याचिका नहीं ली गई है। "उसके ज्ञान के बिना" अभिव्यक्ति का सरल अर्थ है इस तथ्य की अज्ञानता कि उसे जो दिया जा रहा है वह एक मादक पदार्थ है या उसमें है या उसके साथ मिलाया गया है।

नशे की लत के बचाव का लाभ केवल तभी उठाया जा सकता है जब नशा ऐसी स्थिति पैदा करता है की आरोपी अपराध के लिए आवश्यक इरादा खो देता है। नशे के कारण के बारे में सबूत की जिम्मेदारी आरोपी पर है जिसके कारण आरोपी विशेष इरादे को बनाने में विशेष ज्ञान रखने में असमर्थ हो गया था। मूल रूप से, आई. पी. सी. की धारा 85 के दायरे और दायरे के संबंध में तीन प्रस्ताव इस प्रकार हैं

(i) पागलपन चाहे वह शराब पीने से पैदा हुआ हो या अन्यथा, आरोपित अपराध का बचाव;

(ii) शराब के नशे में होने का सबूत जो आरोपी को अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक विशिष्ट इरादे को बनाने में असमर्थ बनाता है, उसे अन्य तथ्यों के साथ ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उसका यह इरादा था या नहीं; और

(iii) नशे में होने का सबूत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक इरादे को बनाने के लिए आरोपी में एक सिद्ध अक्षमता से कम हो जाता है और केवल यह स्थापित करता है कि उसका दिमाग शराब से प्रभावित होता है ताकि वह कुछ हिंसक जुनून को अधिक आसानी से अंजाम दे सके उसके कार्यों के परिणाम को, इस धारणा का खंडन नहीं करता है कि एक आदमी प्राकृतिक इच्छा रखता है।

तत्काल मामले में, नशे की लत की दलील कभी भी आरोपी के क्रूर, शैतानी कृत्यों का बहाना नहीं हो सकती है। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय उन्होंने मामले को दुर्लभतम से दुर्लभतम श्रेणी में आने वाले मामले के रूप में उचित रूप से माना है जिससे मौत की सजा सुनाई गई है।

अभियुक्त द्वारा किए गए क्रूर कार्य-अपील और निष्पादन में क्रूरता। ये कृत्य केवल क्रूर ही नहीं थे बल्कि अमानवीए भी थे जिसके लिए लिए कोई पछतावा नहीं है। केवल इसलिए कि वह प्रासंगिक बिंदु पर दवाब डालता है की कृत्य के समय वह नशे की हालत में था, वह किसी भी तरह से आई. पी. सी. की धारा 85 में क्या प्रावधान किया गया है उसकी वजह से कम गंभीर नहीं नहीं हो जाता, लेकिन क्योंकि एक के बाद एक पाँच जिंदगियाँ ली गयी थी और वह भी चार छोटे बच्चों की। इसलिए हर प्रकार से यह मामला दुर्लभतम श्रेणी के तहत आता है जिसमें मृत्युदंड की आवश्यकता है।

अपील खारिज होने के योग्य है जिसे हम खारिज करने का आदेश देते हैं।

बि.के

शांभवी शंकर